पाँचवें दिव्य हिमगिरि टॉपर्स कॉन्क्लेव में 271 छात्रों को दिए मेडल और अवॉर्ड सर्टिफिकेट

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 11 | मूल्य 15 रुपये | 03-09 अगस्त, 2025

पीएम मोदी-ट्रंप की बिगड़ी केमिस्ट्री से दोराहे पर 'भारतीय बाजार'

वर्ष 15 | अंक 11

दिव्य हिमगिरि

03-09 अगस्त, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित। संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

चुनाव और नागरिकता प्रमाण पत्र पर विवाद

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा है, जिसकी शक्ति निष्पक्ष चुनाव और जन-भागीदारी में निहित है। चुनाव आयोग इस व्यवस्था का आधार है, जो हर नागरिक के स्वतंत्र और स्वेच्छा से मतदान करने के अधिकार की रक्षा करता है। मगर इसकी कार्यप्रणाली पर ही अगर मतदाताओं को संशय होने लगे तो स्पष्टता की मांग स्वाभाविक है। बिहार में कुछ माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और निर्वाचन आयोग ने वहां मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद आयोग की ओर से तय किए गए नागरिकता के प्रमाण पत्रों को लेकर है, जिनमें आधार और मतदाता पहचान पत्र मान्य नहीं बताया गया। इससे मतदाताओं में असंतोष पैदा हुआ। विपक्षी दल भी चुनाव आयोग के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई दलील के आधार पर शीर्ष अदालत को भी कहना पड़ा कि अगर विशेष गहन पुनरीक्षण में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक, इस प्रक्रिया के दौरान राज्य में पंजीकृत पैंसठ लाख लोगों ने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए हैं, क्योंकि वे या तो मृत हैं या स्थायी रूप से कहीं और स्थानांतरित हो गए हैं। यानी अगर इन लोगों की ओर से आने वाले दिनों में कोई आवेदन दायर नहीं किया जाता है, तो उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। हालांकि, आयोग कह चुका है कि मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में फर्जी नामों का पंजीकरण है, जिसे दुरुस्त करना जरूरी है और यह प्रक्रिया देश भर में चलाई जाएगी। मगर सवाल इस प्रक्रिया के समय और बिहार से इसकी शुरूआत करने को लेकर भी है। विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों की दलील है कि चुनाव से ठीक पहले यह कदम उठाना अनुचित है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो लोग किसी कारणवश अपनी नागरिकता का वैध दस्तावेज समय पर नहीं दे पाएंगे, वे मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर पहले सुझाव दिया था कि चुनाव आयोग को इस प्रकिया में नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी शामिल करने पर विचार करना चाहिए। अब आयोग की दलील है कि वह पहचान के उद्देश्य से आधार और मतदाता पहचान पत्र का उपयोग कर रहा है, लेकिन ये दोनों नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि जब किसी बैंक में खाता खुलवाने से लेकर रसोई गैस के लिए पंजीकरण के वास्ते आधार अनिवार्य है, तो वह नागरिकता की प्रमाणिकता के लिए वैध दस्तावेज क्यों नहीं है? मतदाता पहचान पत्र तो चुनाव आयोग की निगरानी में ही बनते हैं, फिर उन्हें भरोसे का दस्तावेज क्यों नहीं माना जा रहा? फिर आयोग की सूची में जिस आवासीय प्रमाणपत्र को जगह दी गई, उसकी हालत यह है कि बिहार के मसौढ़ी से एक कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी करने की खबर आई। ऐसे में किस प्रमाणपत्र को सबसे विश्वसनीय माना जाएगा? यह सच है कि देश में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया जरूरी है। मगर इस प्रक्रिया की जटिलता से कोई योग्य मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग पर ही है।

कुँवर राज अस्थाना

भारत की गिरती प्रजनन दरः एक नये संकट की दस्तक

लम्बे समय से जनसंख्या नियंत्रण भारत की नीतियों का केन्द्र रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आज का युवा न तो संतान चाहता है, न परिवार का बोझ। सरकारी रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की चेतावनियां यह बता रही हैं कि यदि वर्तमान रूझान बना रहा, तो भारत की आबादी वर्ष 2100 तक 80 करोड़ पर सिमट सकती है-जिसमें 30 से 40 करोड़ लोग वृद्ध होंगे। पेश है इस ज्वलंत विषय पर इस अंक का सामयिकी लेख...

लेखकः दीपेन्द्र कुमार चौधरी

विषय पढ़ने में अटपटा जरूर लगता है और इस पर अमुमन चर्चा नहीं होती और ना ही हमारा ध्यान जाता है। यह विषय है- भारत में प्रजनन दर का निरन्तर कम होना। भारत, जिसे हाल ही विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश घोषित किया गया है, एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है जिसकी आहट अभी धीमी है, लेकिन परिणाम दूरगामी और गहरे होंगे। यह संकट है- गिरती प्रजनन दर। जहां पहले भारत में जनसंख्या विस्फोट चिन्ता का विषय था, वहीं अब भविष्य में जनसंख्या में कमीं चिन्ता का विषय बन रही है। कुछ ऐसे स्थानों से तो भविष्य हेतु प्रभावी नीति बनाने की मांग भी उठने लगी है।

लम्बे समय से जनसंख्या नियंत्रण भारत की नीतियों का केन्द्र रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आज का युवा न तो संतान चाहता है, न परिवार का बोझ। सरकारी रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की चेतावनियां यह बता रही हैं कि यदि वर्तमान रूझान बना रहा, तो भारत की आबादी वर्ष 2100 तक 80 करोड़ पर सिमट सकती है-जिसमें 30 से 40 करोड़ लोग वृद्ध होंगे। विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत के सामने एक नया और गंभीर संकट धीरे-धीरे दस्तक दे रहा है-वह है गिरती हुई प्रजनन दर।

भारत में प्रजनन दर बहुत तेजी से घटकर 1-9 प्रतिशत पर आ गयी है। युनाईटेड नेशन्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुसार जनसंख्या समान स्तर पर बनाये रखने के लिए 2-1 प्रतिशत की सब्सीटीट्यूशन रेट (प्रजनन दर) की आवश्यकता होती है। यदि यह दर 2-1 से नीचे आती है तो कुल जनसंख्या में गिरावट प्रारम्भ हो जाती है। विश्व के कई देशों में प्रजनन दर एक प्रतिशत से लेकर 1-25 या 1-5 प्रतिशत पर आ गयी है जो कि खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। कोरिया एवं जापान में तो स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी है, जिस कारण वहां तेजी से जनसंख्या घट रही है और आगामी आने वाले कुछ वर्षों में जनसंख्या की बड़ी आबादी वृद्ध लागों की हो जायगी। इस कारण से वर्कफोर्स तेजी से कम हो रही है। भारत में वर्तमान में युवा लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। कुल आबादी 140 करोड़ के सापेक्ष 90 करोड़ युवा हैं (जो कार्य करने के लिए सक्षम है)। इस 90 करोड़ में से 45 करोड़ पुरूष और 45 करोड़ महिलायें हैं, परन्तु इसमें महिलाओं का योगदान केवल 20 प्रतिशत है, यानि प्रत्येक 5 महिलाओं में से एक महिला कार्य कर रही है। इसमें घरेलू कार्य सम्मिलित नहीं है, यानि प्रत्येक 5 में से 4 महिलायें जॉब एवं बिजनेस नहीं कर रही हैं। इसी प्रकार पुरूषों में प्रत्येक 5 लागों में से 4 लोग कार्य कर रहे हैं। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो भारत में उपलब्ध कुल वर्कफोर्स में से केवल 50 प्रतिशत लोग जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें इन 45 करोड़ वर्कफोर्स में से 36 करोड़ पुरूष और 9 करोड़ महिलायें हैं। दूसरे शब्दों में महिलाओं के सापेक्ष चारगुना ज्यादा पुरूष काम कर रहे हैं। भारत में केवल चार राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में प्रजनन दर 2-1 प्रतिशत से ऊपर है, जिसमें बिहार में प्रजनन उच्च स्तर 3 प्रतिशत के आसपास है और अन्य तीन राज्यों में 3-0 प्रतिशत से नीचे परन्तु 2-1 प्रतिशत से ऊपर है। भविष्य में भारत में वर्ष 2050 में प्रजनन दर वर्तमान 1-9 प्रतिशत से गिरकर 1-3 प्रतिशत पर आ जायगी, यानि आगामी कुछ वर्षों में भारत की जनसंख्या में गिरावट प्रारम्भ हो जायेगी। ऐसी स्थिति में भारत में प्रजनन दर पर दबाव बनना प्रारम्भ हो चुका है और कुछ स्थानों से कुछ लागों द्वारा मांग की जा रही है कि प्रजनन दर बढ़ायी जाय। चीन द्वारा अपनी प्रजनन दर को नियंत्रित किया गया था और सिंगल चाइल्ड नॉर्म को अपनाया था, परन्तु आज चीन को इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। उसकी वर्कफोर्स निरन्तर तेजी से कम हो रही है। वर्ष 2023 में कोरिया में प्रजनन दर गिरकर 0-7 प्रतिशत पर आ गयी है और वहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। इसी तरह की परिस्थिति जापान में भी देखने को मिल रही है। वहां पर वर्ष 2024 में मात्र 6 से 7 लाख बच्चों ने जन्म लिया, जबकि जापान की आबादी 12 करोड़ के आसपास है। जापानी लोग भी बच्चे पैदा करने में रूचि नहीं ले रहे हैं।

प्रजनन दर में गिरावट जब सब्सीटीट्युशन रेट 2-1 प्रतिशत से नीचे आ जाती है, तो इसे नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज यदि हम भारत में भी देखें तो किसी भी परिवार में 4-5 बच्चे देखने को नहीं मिलते हैं और अब तो स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि ढूंढने पर भी कुछ

ही परिवार मिलेंगे, जहां पर मात्र दो बच्चे हैं। यदि बच्चे कम पैदा करने के बारे में जानकारी हासिल की जाये, तो लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, और एक बच्चे की भी पढ़ाई-लिखाई, पालन-पोषण आदि का खर्च उठाना दूभर हो गया है। यह लागत विगत वर्षों में कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। यदि इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो भारत में भी आगामी 25 से 30 वर्षों में आबादी घटना शुरू हो जायगी और लगभग जापान एवं कोरिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जायगी और वृद्धों की आबादी में तेजी से वृद्धि होगी तथा नौजवानों की आबादी कम होती जाएगी। आज भारत में 90 करोड़ लोग काम कर सकते हैं, परन्तु इसमें भी केवल 45 करोड़ ही काम कर रहे हैं। यानि हम 90 करोड़ वर्कफोर्स होने के बावजूद भी केवल हम आधी वकर्फोर्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज लेबर की कमी हर स्थान पर देखने को मिलती है और यदि लेबर मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है। केवल आधी उपलब्ध वर्कफोर्स का ही इस्तेमाल होने के कारण अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा भारत में भी वृद्धजनों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। आज 13 से 15 करोड़ लोग वृद्ध हैं और 2050 तक इनकी संख्या में तेजी से इजाफा हो जायेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जनसंख्या समुदाय के लिए उनके स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली जैसे-पेंशन आदि का भी अतिरिक्त बोझ अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

गिरती प्रजनन दर के कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण बदलते हुए परिवार एवं उसकी संरचनायें भी हैं। परिवार का आकार छोटा (न्यूक्लियर फैमली) हो गया है। दादा-दादी, चाचा-चाची आदि अब यह लोग परिवार में नजर ही नहीं आते हैं, सब अलग रहते हैं। घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उसे क्रेच में डाल देते हैं, जो हमारी पारम्परिक संयुक्त परिवार प्रणाली को एकदम खत्म कर रहा है। आज संयुक्त परिवार किसी छोटे कस्बे या गांव में मौजूद हों, तो यह बड़ी बात है। आजकल के नौजवान शादी नहीं करना चाहते हैं, और यदि शादी करते भी हैं, तो इतनी देर से करते हैं कि तब तक उनकी आयु 30 से 35 वर्ष हो जाती है। कहते हैं पहले कैरियर बनाना है, कैरियर बन जाता है तो शादी करेंगें। जब कैरियर बन जाता है तो उपयुक्त लड़का-लड़की नहीं मिल पाते। यदि देरी से मिलते हैं तो तब तक उनकी आयु 30-35 या 40 वर्ष हो जाती है। इस आयु में शादी करने पर अधिकतर दम्पत्ति बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए और यह भी एक बहाना बन जाता है। इस बड़ी उम्र में काफी लोग वर्क लोड एवं स्ट्रैस के कारण अपनी प्रजनन क्षमता गवां देते हैं। अध्ययन इंगित कर रहे हैं कि आईटी वर्ल्ड और अत्याधिक मोबाईल यूज एवं गलत लाईफ स्टाईल जीने वाले नौकरीपेशा युवकों में से 2 में से एक किसी न किसी रूप में अपने में सैक्सुअल इन्सफिसियन्सी महसूस करता है। वह अपने को वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां निभाने में अक्षम पाता है। यह स्थिति लड़के-लड़कियों के साथ एक हकीकत है। समाज में सिंगल पैरेन्ट्स फैमिली का भी नया चलन फैशन में आ गया है। बच्चे के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची एवं भाई-बहिन उसके पास नहीं होते हैं। इससे भी परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो रहा है। सगे चाचा-चाची, बुआ-फुफा, मामा-मामी, मौसा-मौसी एवं भाई-बहिन के रिश्ते भी तेजी से समाप्त हो रहे हैं। इसके दुष्परिणाम यह हैं कि बिना पारिवारिक रिश्ते के जो संयुक्त परिवार इन बच्चों को सामाजिक, वैचारिक एवं मानसिक सुरक्षा प्रदान करते आ रहे थे, बच्चा उसके अभाव में पलता-बढ़ता है। इससे बच्चे को समाज में एडजस्ट होने में एवं परिवार में अकेले होने के कारण जीवन की कठिनाईयों का सामना करने में मुश्किल आती है। वर्ष 2050 में भारत की प्रजनन दर वर्तमान 1-9 से घटकर 1-29 पर आ जायेगी। यह स्थिति गांव व शहर दोनों जगह समान रूप में देखने को मिलेगी। युवा आबादी जो हमारे आर्थिक विकास का स्तम्भ रही है, अब खतरे में आती जा रही है। अधिकतर परिवारों में बच्चे ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलेंगे।

यद्यपि आज भी भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं, परन्तु इस वर्कफोर्स का केवल 50 प्रतिशत ही काम कर रहे हैं। कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, और जो अधिकतर युवा काम कर भी रहे हैं तो उनमें आवश्यक स्किलसैट की कमी है, जिसके कारण उत्पादकता में कमी (Low Productivity) है। जीवन जीने की लागत वर्तमान में कई गुना बढ़ गयी है और इसी प्रकार बच्चों की पढ़ाई एवं स्वास्थ्य सुविधायें आदि भी कई गुना महंगे हो गये हैं। इसके साथ-साथ जीवन की अनिश्चितायें भी बढ़ गयी हैं। यह कारण कहीं न कहीं युवा लोगों को माता-पिता बनने से रोक रहे हैं। माता-पिता अपने जीवनयापन और बच्चों के लालन-पालन, पढ़ाई, स्वास्थ्य आदि के बीच संतुलन नहीं बना पा रहे हैं और बच्चे पैदा करने के प्रति अरूचि प्रदर्शित कर रहे हैं।

बच्चों के लालन-पालन में दो बड़े खर्चे हैं- शिक्षा और स्वास्थ्य। विगत वर्षो में इन खर्चों में कई गुना बढ़ोत्तरी हो गयी है। महंगाई के कारण माता-पिता अपना एवं बच्चों के जीवनयापन करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार बच्चों की अच्छी पढ़ाई-लिखाई एवं अच्छे नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करके इस गिरती प्रजनन दर को रोक सकती है। माता-पिता का विश्वास रहेगा कि उनके बच्चों के लालन-पालन और देखभाल के लिए सरकार उनके साथ है। कुछ इसी प्रकार के सरकारी इन्सेंटिव जापान, कोरिया एवं अन्य देशों में दिये जा रहे हैं। यद्यपि इसे लागू करवा पाना उतना आसान भी नहीं होगा, जब तक दम्पत्ति अपना कुल धर्म ना निभायें। एक विकल्प यह भी हो सकता है कि हम 'मात्रा' पर न जाकर 'गुणवत्ता' पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करें। सरकार यह भी कर सकती है कि विश्व के समस्त 'अप्रवासी भारतीयों' (NRIs) को भारत की रेगुलर नागरिकता प्रदान कर दी जाय और वह समस्त सुविधाऐं जो भारतीय नागरिक को प्राप्त होती हैं, उन्हें भी उपलब्ध करा दी जायें। इससे न केवल हाइली क्वालीफाइड, टेक्निकली एजुकेटेड प्रोडक्टिव आबादी मिलेगी, बल्कि इसके साथ-साथ आर्थिक रूप से मजबूत लोगों का भी समावेश आबादी में किया जा सकता है।

आज यदि हमने जनसंख्या स्थिरता को लेकर गंभीर मंथन और रणनीतिक योजना नहीं बनायी तो भारत एक बुर्जुग राष्ट्र में तब्दील हो जायेगा। संतान बोझ नहीं बल्कि विकास की धुरी है। सरकार, समाज, नीति निर्माता और नागरिक सभी को मिलकर समझना होगा कि अगली पीढ़ी को खोकर हम केवल जनसंख्या नहीं बल्कि अपना भविष्य भी खो देंगे। यदि हम आज नहीं चेते, तो कल केवल पछतावा शेष रहेगा। सामाजिक अभियान और नीति निर्माण के माध्यम से पारम्परिक संयुक्त परिवार को फिर से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और अन्य आवश्यक उपाय जो संभव हो सकें, को भी अपनाये जाने की जरूरत है।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, समसामयिक विषयों के लेखक एवं विचारक, जो वर्तमान में सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, सैनिक कल्याण एवं सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन में कार्यरत हैं)

पीएम मोदी-ट्रंप की बिगड़ी केमिस्ट्री से दोराहे पर 'भारतीय बाजार'

अंतरराष्ट्रीय मंच पर कभी 'मित्रता की मिसाल' माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों में आई तल्खी अब भारत की अर्थव्यवस्था और बाजार पर भी अपनी छाप छोड़ती नजर आ रही है। ट्रंप की 'टैरिफ' नीति ने भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं डॉलर की चाल और निवेश की अनिश्चितता ने शेयर बाजार को झटका दिया है। दोनों नेताओं के बीच कभी दिखने वाली गर्मजोशी अब रणनीतिक दूरी में बदलती दिख रही है। अमेरिकी नीतियों में आए सख्त रुख और व्यापारिक शर्तों में फेरबदल ने भारतीय बाजार को दोराहे पर ला खड़ा किया है। जहां न तो दोस्ती से राहत दिख रही है और न ही व्यापार से स्थिरता। इस बीच, विपक्ष को भाजपा सरकार को घेरने का सुनहरा मौका मिल गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि क्या 'हाउडी मोदी' जैसे इवेंट्स महज दिखावा थे? उन्होंने यह भी पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को निजी दोस्ती की बजाय राष्ट्रीय हितों पर आधारित रणनीति से क्यों नहीं साधा गया? जहां सरकार अभी भी व्यापार और कूटनीति के संतुलन का दावा कर रही है, वहीं बाजार की नब्ज कुछ और ही कहानी कह रही है। निवेशकों की सतर्कता, रुपये की गिरावट और टैरिफ से जुड़े असमंजस के बीच भारत की आर्थिक दिशा फिलहाल एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। जहां हर कदम सियासत से भी जुड़ा है और बाजार की चाल से भी।

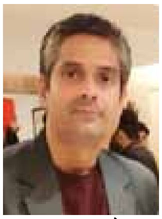

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए भारी भरकम 'टैरिफ' के बाद भारतीय बाजार सहमा हुआ है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर तंज कस रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार और देशवासी भी प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती कैसे और क्यों बिगड़ी जानकर हैरान हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पीएम मोदी और भाजपा के नेता चुप्पी बनाए हुए हैं वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर है। इन सब के बीच ट्रंप की टैरिफ से भारत के बाजार में हलचल है। इसी महीने 7 अगस्त को अमेरिका की भारत पर टैरिफ नीति लागू हो रही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत और अमेरिका के रिश्तों को लंबे समय तक 'मित्रता की मिसाल' कहा गया। विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी को वैश्विक मंच पर खास पहचान मिली। 'हाउडी मोदी' (ह्यूस्टन,

2019) और 'नमस्ते ट्रंप' (अहमदाबाद, 2020) जैसे आयोजन केवल राजनीतिक समारोह नहीं, बल्कि दो वैश्विक लोकतंत्रों की निकटता के प्रतीक बने। लेकिन समय के साथ हालात बदल गए हैं। वर्ष 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिकी चुनावी परिदृश्य में प्रमुख भूमिका में लौटे हैं, तब उनके नीति रुख में आई सख्ती और भारत के प्रति बदली हुई भाषा ने इस संबंध को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। ट्रंप की घोषित टैरिफ नीति, जिसमें आयात पर भारी शुल्क लगाने की बात कही जा रही है, भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विषय बन गई है। अमेरिकी बाजार में भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा आता है, चाहे वह फार्मास्युटिकल्स हों, ऑटो पार्ट्स, स्टील उत्पाद, या फिर आईटी सेवाएं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया गया था, जिससे कई निर्यातकों को नुकसान झेलना पड़ा। अब जब वह फिर से वही रुख अपनाने के संकेत दे रहे हैं, तो भारत के निर्यातक वर्ग में असमंजस और भय साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस नई टैरिफ नीति के संकेत मिलते ही भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता देखी गई है। विदेशी निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा है, और डॉलर की मजबूती के साथ ही भारतीय रुपया दबाव में है। पिछले दो हफ्तों में रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 84.75 के स्तर तक पहुंच चुकी है, जो निवेशकों के लिए चिंता का कारण बन रहा है। स्टॉक मार्केट के प्रमुख इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखी गई, खासकर उन कंपनियों के शेयरों में जो अमेरिका पर निर्भर व्यापार करती हैं। इस बदले परिदृश्य में भारत की कूटनीतिक रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस, ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि 'हाउडी मोदी' जैसे कार्यक्रम केवल व्यक्तिगत छवि चमकाने की कवायद थे, और इनसे देश के व्यापारिक या रणनीतिक हितों को कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विदेश नीति को निजी संबंधों पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर आधारित होना चाहिए, और वर्तमान सरकार इस संतुलन को साधने में असफल रही है। अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि भारत की विदेशी नीति में स्थायित्व की कमी दिखाई दे रही है। जहां एक ओर सरकार वैश्विक मंचों पर 'वसुधैव कुटुंबकम' की बात करती है, वहीं व्यापारिक स्तर पर भारत अब तक किसी स्पष्ट दिशा में बढ़ता नहीं दिख रहा। विशेषकर अमेरिका जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ, जहां व्यापार घाटा लगातार बना हुआ है, भारत को अब एक नई रणनीति की आवश्यकता महसूस हो रही है। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई सीधा बयान नहीं आया है, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने बंद कमरे की बैठकों में संभावित रणनीतियों पर चर्चा शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि भारत अमेरिका के साथ फिर से व्यापार वार्ता को सक्रिय करने की कोशिश करेगा, जिससे टैरिफ से जुड़ी चिंता को कम किया जा सके। साथ ही, यूरोप और दक्षिण एशियाई देशों के साथ वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों को भी तेजी से मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है। धीमी विकास दर, बेरोजगारी, कृषि संकट और अब वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच टैरिफ नीति से उपजा नया तनाव इन समस्याओं को और बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में सुधार नहीं हुआ, तो इसका सीधा असर भारत की जीडीपी पर भी पड़ेगा, खासकर निर्यात आधारित क्षेत्रों पर। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकार यह भी कह रहे हैं कि भारत को अब इस सोच से बाहर निकलना होगा कि किसी एक नेता के साथ मजबूत रिश्ता पूरी विदेश नीति को संभाल सकता है। विश्व राजनीति में स्थायित्व और विविधता का सिद्धांत अपनाना समय की मांग है। अमेरिका में अगर सत्ता में परिवर्तन होता है, तो नीति भी बदल जाती है, और भारत को इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। दूसरी ओर, अमेरिका में भी ट्रंप की नीतियों को लेकर दो धड़े हैं। एक वर्ग का मानना है कि उनका 'अमेरिका फर्स्ट' दृष्टिकोण घरेलू उद्योगों के लिए बेहतर है, वहीं दूसरे वर्ग का मानना है कि यह नीति वैश्विक सहयोग को कमजोर करती है और अमेरिका की नेतृत्व भूमिका को नुकसान पहुंचाती है। भारत को इस अंतर का लाभ उठाने की आवश्यकता है। यदि वह अमेरिका के भीतर के उदारवादी वर्ग के साथ संवाद बनाए रखे, तो द्विपक्षीय संबंधों में संतुलन कायम रह सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक व्यापक राजनीतिक पहलू भी है। वर्ष 2025 में जब भारत में आम चुनाव नजदीक हैं, तब यह मुद्दा विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का एक प्रमुख हथियार बन गया है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर

ट्रंप पाकिस्तान-चीन को खुश करने में लगे, भारत समेत 70 देशों पर लगाया टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति दुनिया के तमाम देशों के बाजारों में हलचल मचा रखी है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल लिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से ज्यादा महत्व पाकिस्तान और चीन को दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से कम पाकिस्तान पर टैरिफ लगाया है वहीं चीन का इस लिस्ट में नाम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारतीय बाजार को नियंत्रण में लेना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैए से केंद्र सरकार फिलहाल ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद भारतीय बाजार में हलचल जरूर है। देश का व्यापार जगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर टकटकी लगाए हुए इंतजार कर रहा है कि शायद कोई नई उम्मीद निकले जिससे उन्हें भारी भरकम टैरिफ से राहत मिल सके। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसी उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय के बाद चीन और पाकिस्तान के बाजार सामान्य हैं। साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा है। वहीं दुनियाभर में सबसे ज्यादा 41: टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है। इस लिस्ट में चीन का नाम शामिल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 से 41 प्रतिशत के रेसिप्रोकल टैरिफ वाले फैसले पर साइन कर दिए हैं। इसी महीने 7 अगस्त को भारत समेत 70 देशों में टैरिफ की नई दरें लागू कर दी जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात पर 25 फीसदी, ताइवान पर 20 फीसदी और दक्षिण अफ्रीका पर 30 फीसदी टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं अमेरिका के व्यापार सहयोगियों के साथ संबंधों को लेकर भी यह संकट की घड़ी कही जा सकती है।

सरकार की छवि और नीतियों की समीक्षा अब केवल संसद या मीडिया तक सीमित नहीं, बल्कि जनता के राजनीतिक मूड को भी प्रभावित कर सकती है। मोदी सरकार ने भले ही अब तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान नहीं दिया हो, लेकिन चुनावी मंचों पर इसे लेकर जवाबदेही तय करने की तैयारी विपक्ष ने शुरू कर दी है। अंततः यह स्पष्ट है कि भारत-अमेरिका संबंध अब केवल मंचीय फोटो और बड़े इवेंट्स से नहीं चल सकते। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को दीर्घकालिक रणनीति, आर्थिक चतुराई और बहुपक्षीय सहयोग को साथ लेकर चलना होगा। निजी मित्रता और सार्वजनिक कूटनीति के बीच की दूरी को समझते हुए अब आवश्यक है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए ऐसी नीति अपनाए, जो केवल एक नेता के जाने या आने से प्रभावित न हो। भारत की आर्थिक दिशा इस समय एक नाजुक दौर से गुजर रही है। निवेशकों की बेचैनी, रुपये की कमजोरी और निर्यात बाजार के सिमटते अवसर यह संकेत देते हैं कि अब समय है जब 'मित्रता की मिसाल' से आगे बढ़कर 'रणनीतिक संतुलन' की मिसाल गढ़ी जाए। यही भविष्य की स्थिरता और भारत के वैश्विक आर्थिक नेतृत्व का आधार बन सकता है। वहीं दूसरी ओर शनिवार 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ पर सार्वजनिक मंच से अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25 परसेंट टैरिफ पर करारा जवाब दिया। पीएम ने कहा कि हमारे किसान, छोटे उद्योग, और युवाओं के रोजगार हमारे लिए सर्वोपरि हैं। सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। पीएम ने जोर देकर कहा कि वैश्विक अस्थिरता के माहौल में भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सतर्क रहना होगा। उन्होंने 'स्वदेशी' उत्पादों को बढ़ावा देने और 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को अपनाने का आहवान किया, ताकि भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता मिले।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाए जाने पर भाजपा घिरी विपक्षी घेराबंदी में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कभी चर्चित रही मित्रता अब विपक्ष के लिए एक नया हथियार बनती दिख रही है। मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया है। विपक्ष ने संसद में सवाल दागते हुए सरकार की विदेश नीति पर सीधा हमला बोला और पूछा कि क्या अंतरराष्ट्रीय मंच पर आयोजित 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रंप' जैसे आयोजन केवल दिखावटी थे? संसद के दोनों सदनों में इस पर तीखी बहस देखने को मिली। अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। संसद के मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यक्तिगत दोस्ती की बजाय राष्ट्रीय रणनीति पर आधारित ठोस कूटनीति की जरूरत थी, जो मोदी सरकार नहीं कर सकी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिश्तों को भारत-अमेरिका संबंधों का आधार बना दिया। 'हाउडी मोदी' जैसे इवेंट्स को कूटनीति का विकल्प बना दिया गया। लेकिन जब ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के खिलाफ हो गई, तब सरकार के पास कोई तैयारी नहीं दिखी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने विदेश नीति को प्रचार का माध्यम बना दिया और वास्तविक आर्थिक हितों की अनदेखी की। आज हमारे निर्यातकों को नुकसान हो रहा है, रुपया गिर रहा है, निवेशकों में डर है। और प्रधानमंत्री खामोश हैं। यह सब उनके 'मित्र कूटनीति' के नतीजे हैं राहुल गांधी ने कहा। राहुल ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौतों की जानकारी संसद को क्यों नहीं देती। आपने देश को नहीं बताया कि अमेरिका के साथ क्या डील की, किन शर्तों पर की, और अब जब वही अमेरिका भारत पर टैरिफ का बोझ डाल रहा है तो आप चुप क्यों हैं? कांग्रेस नेता ने मांग की कि प्रधानमंत्री खुद संसद में इस मुद्दे पर सफाई दें और यह स्पष्ट करें कि भारत की विदेश व्यापार नीति आगे किस दिशा में जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर ऐसी विदेश नीति बनाई जाएगी जो किसी एक व्यक्ति की मित्रता पर नहीं, बल्कि संस्थागत हितों और दीर्घकालिक रणनीति पर आधारित होगी।

अमेरिकी टैरिफ नीति से भारत को हो रहे संभावित आर्थिक नुकसान को लेकर राहुल गांधी ने इसे एक 'डिप्लोमैटिक फेल्योर' बताया है और कहा है कि देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा, 'जब अमेरिका से दोस्ती की तस्वीरें खिंचवाई जा रही थीं, तब सरकार ने यह क्यों नहीं सोचा कि यह रिश्ता ट्रंप की सत्ता से बाहर जाते ही कमजोर हो जाएगा? मोदी जी की व्यक्तिगत मित्रता देश की कूटनीति नहीं हो सकती।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को 'इवेंट मैनेजमेंट' की तरह लिया और अब जब अमेरिकी टैरिफ नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है, तब सरकार मौन है। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से जवाब मांगा कि क्यों ट्रंप के साथ दिखने वाली करीबी अब रणनीतिक दूरी में बदल गई है। उन्होंने कहा, 'सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अमेरिका के साथ हमारे व्यापारिक और रणनीतिक संबंध किस दिशा में जा रहे हैं। क्या मोदी-ट्रंप की दोस्ती सिर्फ कैमरे तक सीमित थी? 'तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी' ने भी इस

विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है टैरिफ

टैरिफ का अर्थ है वह कर या शुल्क जो किसी देश की सरकार विदेश से आने वाले सामान यानी आयात (इंपोर्ट) पर लगाती है। जब कोई वस्तु एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती है और वहां के बाजार में बिकती है, तो उस पर एक अतिरिक्त लागत जुड़ जाती है। इसी लागत को टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ लगाने का मकसद आम तौर पर दो होता है। एक, विदेशी वस्तुओं को महंगा बनाकर घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना और दूसरा, सरकार को राजस्व प्राप्त करना। जब अमेरिका जैसे बड़े देश अपनी टैरिफ नीति बदलते हैं, यानी किसी देश से आने वाले सामान पर शुल्क बढ़ा देते हैं, तो उसका सीधा असर उस देश के निर्यातकों पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर भारत से अमेरिका को भेजे जा रहे स्टील या दवाओं पर वहां की सरकार भारी टैरिफ लगा देती है, तो वे वस्तुएं अमेरिकी बाजार में महंगी हो जाएंगी और कम खरीदी जाएंगी। इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान होता है, उनकी प्रतिस्पर्धा घटती है और देश के कुल निर्यात पर असर पड़ता है। टैरिफ का प्रभाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहता। जब निर्यात कम होता है, तो विदेशी मुद्रा की आमद भी घटती है। इसका असर रुपये की मजबूती पर पड़ता है, शेयर बाजार में निवेशकों की धारणा कमजोर होती है, और देश की समग्र आर्थिक स्थिति अस्थिर हो सकती है। इसीलिए, टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और रणनीति का महत्वपूर्ण औजार भी है। जिसे बड़े देश अक्सर अपने हित साधने के लिए इस्तेमाल करते हैं।

मसले पर सरकार की आलोचना की। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि 'आज जब डॉलर मजबूत हो रहा है, निवेशक भारत से दूरी बना रहे हैं और निर्यातकों में असमंजस है, तब प्रधानमंत्री को संसद में आकर स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी कूटनीतिक नीति किल क्यों हो रही है।' सरकार की ओर से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जवाब में कहा कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को केवल किसी एक राष्ट्रपति के कार्यकाल से नहीं जोड़ता। उन्होंने कहा, 'भारत की नीति राष्ट्रहित आधारित है, न कि किसी नेता की व्यक्तिगत समीकरण पर। जो भी फैसले लिए गए, वे देश के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर किए गए थे।' साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिका के साथ बातचीत की प्रक्रिया लगातार जारी है और टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर वाणिज्य मंत्रालय काम कर रहा है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संकेत दिया कि सरकार वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है और निवेशकों के मनोबल को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम जल्द उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में चुनावी माहौल है, और भारत को किसी भी अस्थायी बयान या नीति से घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मानसून सत्र में कहा, 'मोदी जी ने जिस दोस्ती को 'डिप्लोमैटिक कैश' बताया था, आज वही रिश्ता भारत के लिए आर्थिक बोझ बनता जा रहा है।' उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रधानमंत्री स्वयं इस विषय पर संसद में आकर बयान दें, न कि केवल मंत्रियों के जरिए जवाब भेजें। इन सबके बीच विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-अमेरिका रिश्तों का राजनीतिकरण अब घरेलू राजनीति में भी गहराता जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार इस दोस्ती को रणनीतिक सफलता बताती रही, वहीं अब वही संबंध विपक्ष के लिए मोदी सरकार को घेरने का आधार बन रहा है। संक्षेप में, 'मित्रता की मिसाल' कभी भारत की विदेश नीति की एक खास झलक मानी जाती थी, लेकिन 2025 के मानसून सत्र में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। अमेरिकी टैरिफ नीति और भारत की आर्थिक स्थिति के बीच संसद में उठे सवाल यह दिखाते हैं कि अब समय आ गया है जब इस मित्रता के राजनीतिक नफा-नुकसान पर एक व्यापक मूल्यांकन जरूरी है। ताकि भविष्य की विदेश नीति अधिक संतुलित और दीर्घकालिक हितों पर आधारित हो सके।

डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 29% से 19% किया

अमेरिका के रष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 29: से 19: कर दिया है। इस बदलाव के बाद पाकिस्तान अब पूरे दक्षिण एशिया में सबसे कम टैरिफ वाला देश बन गया है। अमेरिका ने भारत पर 25: और बांग्लादेश पर 20: टैरिफ लगाया है, जिससे पाकिस्तान को रणनीतिक फायदा मिल सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कपड़ा उद्योग है, और अमेरिका उसका सबसे बड़ा खरीदार है। भारत, बांग्लादेश और वियतनाम भी इसी बाजार में हैं, लेकिन उन पर ज्यादा शुल्क लगने से पाकिस्तान को ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि यह फैसला ऊर्जा, खनिज, आईटी और क्रिप्टो जैसे क्षेत्रों में नए आर्थिक सहयोग की शुरुआत करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला पाकिस्तान को आर्थिक रूप से 'स्थिर करने' की एक कोशिश भी हो सकती है। अमेरिका के पाकिस्तान को मिले इस रियायत का फैसला सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरणों के हिस्से के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीते कुछ महीनों में अमेरिकी और पाकिस्तान के रिश्ते में काफी नजदीकी आई है। पाकिस्तान ने जून में ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया था। वहीं, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते में तनाव दिखा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का भारत के साथ भारी व्यापार घाटा है। उन्होंने कहा 'भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। साथ ही किसी भी देश की तुलना में उनके सबसे कठोर गैर-मौद्रिक व्यापार प्रतिबंध हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लाओस, म्यांमार, सीरिया जैसे देशों पर सबसे ज्यादा 40: या उससे ज्यादा टैरिफ लगाया है। अगर कोई वस्तु किसी और देश के जरिए भेजी गई है ताकि टैक्स बचाया जा सके, तो उस पर 40: टैरिफ लगेगा। यूरोपीय संघ के सामानों पर सीधो 15: टैरिफ नहीं लगाया गया। अगर किसी प्रोडक्ट का मौजूदा शुल्क 10: है, तो सिर्फ 5: अतिरिक्त जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट पहले से 15: या उससे अधिक शुल्क दे रहा है, तो कोई टैरिफ नहीं बढ़ेगा। चीन पर अलग से मई 2025 का एक्सिक्यूटिव आर्डर 14298 लागू है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कनाडा पर 1 अगस्त की रात से ही टैरिफ लागू होगा। इसकी वजह ये है कि कनाडा ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर समर्थन देने का एलान किया है। आदेश लागू होने से पहले जो सामान अमेरिका के रास्ते में होगा, उसे पुराने नियमों पर ही टैक्स देना होगा।

पंचायत चुनाव नतीजों ने भाजपा-कांग्रेस की 'जमीनी हकीकत' उजागर की

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के परिणाम सामने आ चुके हैं और इन नतीजों ने राज्य की सियासत में नई करवट की आहट दे दी है। गांव-गांव से आए जनादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि अब मुकाबला सिर्फ शहरी राजनीति तक सीमित नहीं रहा। राजनीतिक दलों की असली पकड़ का इम्तिहान अब ग्रामीण बेल्ट में हो रहा है। जहां कुछ जिलों में भाजपा ने अपनी सांगठनिक मजबूती और सरकार की योजनाओं के बल पर वर्चस्व बनाए रखा, वहीं कई क्षेत्रों में कांग्रेस ने खामोशी से वापसी की दस्तक दी है। कुछ जिलों में निर्दलीय प्रत्याशियों की अप्रत्याशित जीत ने दोनों प्रमुख दलों को आत्ममंथन की स्थिति में ला खड़ा किया है। यह परिणाम न केवल पंचायत स्तर पर सत्ता की तस्वीर तय करते हैं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जनता के मूड का संकेत भी देते हैं। भाजपा के लिए यह एक चेतावनी है कि हर क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की पहुंच समान रूप से असरदार नहीं रही, जबकि कांग्रेस के लिए यह एक मौका है। जमीनी स्तर से संगठन को मजबूत कर फिर से मुख्यधारा में आने का। उत्तराखंड में आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नतीजों पर दिव्य हिमगिरि की विशेष रिपोर्ट।

उत्तराखंड के 12 जिलों में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के नतीजों ने राज्य की सियासी तस्वीर को नया रंग दे दिया है। हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष जिलों में मतदान दो चरणों में 24 और 28 जुलाई को हुआ, जबकि मतगणना 31 जुलाई को हुई। कुल मिलाकर करीब 69 प्रतिशत मतदान हुआ और लगभग 32,580 उम्मीदवार मैदान में थे। यह चुनाव भले ही पार्टी चिह्न पर नहीं होते, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों की गहरी भागीदारी और अंदरखाने की रणनीति साफ नजर आई। भाजपा के लिए यह चुनाव एक मिली-जुली तस्वीर लेकर आया। कुछ जिलों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने जिला पंचायत और ग्राम प्रधान पदों पर प्रभावी प्रदर्शन किया, जिससे यह संकेत मिला कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाएं और संगठनात्मक ताकत अब भी असरदार है। खासकर देहरादून और उधमसिंह नगर जैसे क्षेत्रों में पार्टी को अच्छा समर्थन मिला। हालांकि कई पारंपरिक गढ़ों में भाजपा को अप्रत्याशित झटके भी लगे हैं, जिससे यह सवाल खड़ा हुआ है कि क्या विकास योजनाओं की पहुंच हर गांव तक समान रूप से हो पाई है। यह नतीजे आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक चेतावनी भी हैं कि हर क्षेत्र में संगठन की जमीनी पकड़ को और मजबूत करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए ये चुनाव हल्की उम्मीद की किरण लेकर आए। टिहरी, पौड़ी और चंपावत जैसे कुछ जिलों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जहां पार्टी ने स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हुए डोर-टू-डोर संपर्क साधा। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन राज्यभर में कोई बड़ी लहर जैसा नहीं रहा, लेकिन यह साफ दिखा कि पार्टी का संगठन अब धीरे-धीरे ग्रामीण इलाकों में फिर से सक्रिय हो रहा है। कांग्रेस के लिए यह नतीजे संकेत हैं कि यदि वह अब भी गांव स्तर पर स्थायी रणनीति अपनाए और स्थानीय नेतृत्व को मजबूती दे, तो आगामी चुनावों में वह चुनौती खड़ी कर सकती है। इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बनी निर्दलीय उम्मीदवारों की मजबूत उपस्थिति। कई जिलों में भाजपा और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ते हुए निर्दलीयों ने ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत पदों पर कब्जा जमाया। खासकर रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जैसे जिलों में ऐसे उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की जो केवल अपने काम, छवि और सामाजिक जुड़ाव के बल पर मैदान में उतरे थे। पिथौरागढ़ के क्वीरी जिमियां गांव से 22 वर्षीय ईशा ने ग्राम प्रधान बनकर युवा नेतृत्व की नई मिसाल कायम की, जबकि सीला दुगड्डा सीट से सीमा भंडारी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के मुस्लिम उम्मीदवारों को हराकर नया संदेश दिया कि ग्रामीण जनता अब केवल पार्टी नहीं, उम्मीदवार का चेहरा और काम

न्यायालय का साफ संदेश, ‘भगवा आतंकवाद’ का कोई आधार नहीं

साल 2008 के चर्चित मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष एनआईए कोर्ट ने गुरुवार, 31 जुलाई को पूर्व सांसद साधवी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है। करीब 17 वर्षों की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी को क्लीन चिट दी। यह फैसला जहां भाजपा खेमे में ‘न्याय की जीत’ के रूप में देखा जा रहा है, वहीं कांग्रेस इसे ‘जांच एजेंसियों की किलता और सत्ताधारी दल की साजिश’ बता रही है। भगवा आतंकवाद को लेकर वर्षों से चला आ रहा सियासी नैरेटिव एक बार फिर चर्चा में है, जिससे देश की राजनीति में नया उबाल आ गया है। शंभू नाथ गौतम

महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में गुरुवार, 31 जुलाई साल 2025 को बड़ा फैसला आया। एनआईए की विशेष अदालत ने करीब 17 साल पुराने मामले में भाजपा सांसद साधवी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित और अन्य छह आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में किल रहा और इसलिए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि भगवा आतंकवाद जैसी किसी विचारधारा का कोई प्रमाणिक या कानूनी आधार नहीं है। अदालत के इस निर्णय के बाद ‘भगवा आतंकवाद’ शब्द को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए। यह मामला 29 सितंबर 2008 को मालेगांव, महाराष्ट्र में हुए बम धमाके से जुड़ा है। धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह विस्फोट एक मोटरसाइकिल में लगाए गए विस्फोटक से किया गया था। इस मोटरसाइकिल का लिंक साधवी प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ने पर महाराष्ट्र एटीएस ने उन्हें और कर्नल पुरोहित समेत कई अन्य को गिरफ्तार किया। बाद में यह मामला एनआईए को सौंपा गया और लंबे समय तक जांच और ट्रायल चला। अभियोजन ने दावा किया था कि यह एक संगठित साजिश थी, जिसमें ‘हिंदू चरमपंथी विचारधारा’ से जुड़े लोग शामिल थे। लेकिन अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए सबूत इस दावे को प्रमाणित नहीं करते। कोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसियां यह साबित करने में असफल रहीं कि आरोपियों ने किसी आतंकी संगठन का गठन किया या आतंक फैलाने की मंशा से विस्फोट किया। अदालत ने यह भी कहा कि कुछ गवाहों के बयान या सबूतों में पर्याप्त सामंजस्य नहीं था और आरोपियों की भूमिका को लेकर विश्वसनीयता की कमी थी। इस आधार पर सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। अदालत के इस फैसले का व्यापक राजनीतिक असर भी दिखाई दे रहा है। ‘भगवा आतंकवाद’ शब्द का इस्तेमाल पहली बार 2010 के करीब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने किया था, जब कुछ आतंकी घटनाओं में कथित रूप से हिंदू संगठन के लोगों के नाम सामने आए थे। इसके बाद भाजपा लगातार इस शब्द को लेकर कांग्रेस पर हमला करती रही। अब जब कोर्ट ने इस केस में भगवा विचारधारा को आतंकवाद से जोड़ने के आरोपों को आधारहीन बताया है, तो यह मुद्दा फिर से राजनीतिक अखाड़े में आ गया है। साधवी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित ने पहले दिन से खुद को निर्दोष बताया था और कहा था कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से फंसाया गया है। इस फैसले के बाद उन्होंने कहा कि यह ‘सत्य की जीत’ है और अब उन्हें न्याय मिला है।

भाजपा ने इस फैसले को ‘सत्य की जीत’ बताया और कांग्रेस ने सवाल उठाए

मालेगांव ब्लास्ट केस में अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। भाजपा नेताओं ने इस फैसले को ‘सत्य की जीत’ बताया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वर्षों

तक निर्दोष साधवी प्रज्ञा को झूठे केस में फंसाया गया। उन्होंने कहा, 'आज अदालत ने साबित कर दिया कि भगवा आतंकवाद एक राजनीतिक भ्रम था।' वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्र ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ वोटबैंक के लिए हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश की और 'भगवा' को आतंक का प्रतीक बताने की कोशिश की, जो अब न्यायिक रूप से खारिज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को अब देश से माफी मांगनी चाहिए कि उसने 'राष्ट्रभक्तों को आतंकवादी बताया'। उन्होंने कहा कि यह देश के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर हमला था। योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'यह न्याय की नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की भी जीत है।' उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब कांग्रेस को खुले मंच से क्षमा मांगनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अदालत का यह फैसला केवल व्यक्तियों को दोषमुक्त नहीं करता, बल्कि एक पूरे राजनीतिक नैरेटिव को खारिज करता है, जो वर्षों से समाज में जहर घोलने का काम कर रहा था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से भले इस मुद्दे पर नाम न लिया हो, लेकिन एक कार्यक्रम में कहा, 'जो लोग वर्षों तक सनातन मूल्यों को बदनाम करते रहे, उन्हें आज न्यायालय ने आइना दिखा दिया है।' उन्होंने कहा कि भगवा राष्ट्रसेवा और त्याग का प्रतीक है, उसे आतंक से जोड़ना कांग्रेस की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल रही। मालेगांव ब्लास्ट केस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों का निर्दोष साबित होना कांग्रेस के 'हिंदू आतंकवाद' के नैरेटिव पर करारा प्रहार है। कांग्रेस ने 'भगवा आतंकवाद' जैसे झूठे नैरेटिव से साधु-संतों, सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्तों को बदनाम किया, आज इस निर्णय ने उस पाप का पर्दाफाश किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाए और भाजपा पर 'जांच एजेंसियों को प्रभावित करने' का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 'हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन यह भी मानते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता संदिग्ध रही है।' उन्होंने कहा कि दोषमुक्ति का आधार 'सबूतों का अभाव' है, न कि आरोप झूठे थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बयान दिया कि 'इस फैसले से यह सिद्ध नहीं होता कि घटनाएं नहीं घटीं, बल्कि यह साबित करता है कि या तो जांच ठीक से नहीं हुई या जानबूझकर कमजोर की गई।' उन्होंने इसे 'जांच एजेंसियों की किलता' बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जिन्होंने 'भगवा आतंकवाद' शब्द को सबसे पहले राजनीतिक विमर्श में लाया था, फैसले के बावजूद अपने रुख पर कायम रहे। उन्होंने कहा, मैं आज भी अपने शब्दों पर कायम हूं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कुछ घटनाओं में कट्टर संगठनों की संलिप्तता सामने आई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनआईए की जांच जानबूझकर कमजोर की गई और गवाहों पर दबाव डाला गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 'जब आरोपी संसद में बैठा हो, और जांच एजेंसियां सरकार के अधीन हों, तो फैसले पर सवाल उठते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अदालत के निर्णय का सम्मान करती है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल उठाना भी जरूरी होता है। राहुल गांधी ने सीधे इस विषय पर प्रतिक्रिया न देते हुए ट्वीट करते हुए लिखा- सत्य कभी हारता नहीं, देर हो सकती है, लेकिन जीत उसी की होती है।' इसे भाजपा पर तंज के रूप में देखा गया, हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि वे फैसले के कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि 'यह फैसला उन लोगों के लिए राहत हो सकता है जो आरोपी थे, लेकिन यह भी सच है कि समाज में इन घटनाओं की वजह से भय और संदेह का माहौल बना।' उन्होंने कहा कि न्यायालय का निर्णय अंतिम जरूर होता है, लेकिन उस तक पहुंचने वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाना गलत नहीं है। मनीष तिवारी ने भी कहा कि 'यह जांच एजेंसियों की पेशेवर क्षमता पर गंभीर सवाल उठाता है। अगर इतने सालों तक केस चला और फिर सबूत ही नहीं मिले, तो यह जांच का किल होना है या राजनीतिक हस्तक्षेप इसकी जांच होनी चाहिए।' आनंद शर्मा ने यह टिप्पणी की कि 'आतंकवाद को धर्म से जोड़ना हमेशा खतरनाक रहा है, चाहे वह भगवा हो या हरा। लेकिन इस केस का राजनीतिक इस्तेमाल दोनों पक्षों ने अपने-अपने तरीके से किया है यह दुर्भाग्यपूर्ण है।'

17 साल पहले बम विस्फोट के बाद मालेगांव शहर थम गया था

29 सितंबर 2008 की शाम को मालेगांव की तंग गलियों में साइकिल पर रखा एक बम फटता है। शहर थम जाता है। हड़कंप सिर्फ पुलिस तक नहीं, मस्जिदों, मंदिरों और घरों के भीतर तक पहुंचता है। क्योंकि मालेगांव कोई आम शहर नहीं। यह दशकों से हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की मिसाल भी रहा है और सांप्रदायिक तनावों का शिकार भी। उस शाम जब ब्लास्ट हुआ, पीड़ितों में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से थे। क्योंकि हादसा रमजान के महीने में हुआ था, और लोग नमाज के बाद लौट रहे थे। कुछ ही घंटों में गुस्से और शक की दीवारें खड़ी हो गई। हर तरफ एक ही सवाल था। 'अबकी बार कौन?' पहले जहां उंगलियां पाकिस्तान, आईएसआई, सिमी जैसे नामों की ओर उठती थीं, इस बार एनआईए की जांच ने हिंदू संगठनों और सैन्य अधिकारियों तक को लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं से जन्म हुआ उस शब्द का। जो अगले कई सालों तक राजनीति और मीडिया की बहस बना रहा। 'भगवा आतंकवाद।' मालेगांव जैसे कस्बे में हिंदू और मुसलमान कई पीढ़ियों से साथ रहते आए हैं। धार्मिक उत्सव हों या बाजार। एक-दूसरे की दुकानें, रिश्ते, कामकाज। सब में साझेदारी थी। लेकिन ब्लास्ट के बाद जो शक की फिजा बनी, उसने पड़ोसियों को भी पराया बना दिया। मुस्लिम समुदाय को लगा कि एक सोची-समझी साजिश हुई है, और हिंदू समुदाय खुद हैरान था कि उन्हें संदेह की नजर से देखा जा रहा है। जांच के शुरुआती दौर में जैसे-जैसे साधवी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और अन्य नाम सामने आए। कुछ दलों ने इसे त्वरित रूप से 'हिंदू आतंक का मामला' घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर, बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी दलों ने इसे एक समुदाय विशेष को बदनाम करने की साजिश बताया। इस बीच मालेगांव के आम लोगों के लिए सबसे कठिन चीज थी। अपने पड़ोसी को दोबारा भरोसे से देख पाना। 31 जुलाई साल 2025 को अदालत का फैसला आया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए। कहा गया कि पर्याप्त सबूत नहीं हैं। लेकिन क्या यह फैसला उस डर, टूटे रिश्तों और समाज में उपजे अविश्वास को खत्म कर सका? मालेगांव की गलियों में आज भी वो साइकिल की तस्वीरें तैरती हैं, जिस पर बम रखा गया था। वो घर जिनके चिराग बुझ गए। आज भी किसी नाम के इंतजार में हैं। और वो मोहल्ले। जो कभी एक-दूसरे के त्योहारों में साथ हुआ करते थे। अब थोड़े सतर्क, थोड़े अलग हो चले हैं। मालेगांव सिर्फ एक ब्लास्ट का नाम नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जहां एक विस्फोट ने दो समुदायों के बीच की अनकही, अदृश्य दरारों को उजागर कर दिया। और भले ही अदालत ने अब इंसाफ दे दिया हो। दिलों का फैसला अभी बाकी है।

देख रही है। इस बार चुनाव में महिला और युवा उम्मीदवारों ने भी उल्लेखनीय भागीदारी निभाई। देहरादून की माहेश्वरी देवी और आंचल पुंडीर, चमोली की प्रियंका नेगी और साक्षी जैसी प्रत्याशियों ने प्रधान पदों पर जीत दर्ज की। इन नतीजों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण राजनीति में अब महिलाओं और युवाओं की भूमिका निर्णायक बन रही है। मतदाताओं की सोच बदल रही है और वे अब अपेक्षित बदलाव को मौका देना चाहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के यह नतीजे केवल गांवों की सरकार तय नहीं करते, बल्कि यह उस व्यापक राजनीतिक दिशा की झलक भी हैं जो आने वाले समय में राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगी। भाजपा को जहां अपनी सरकारी योजनाओं की जमीनी सच्चाई की समीक्षा करनी होगी, वहीं कांग्रेस के पास यह अवसर है कि वह इन्हीं पंचायतों के सहारे अपनी खोई हुई जमीन दोबारा हासिल करे। और सबसे बड़ी बात, निर्दलीयों की बढ़ती स्वीकार्यता यह संदेश देती है कि गांव अब खुद सोचने और अपने भविष्य का निर्णय लेने की स्थिति में आ चुके हैं, यह लोकतंत्र के लिए सबसे सुखद संकेत है।

भाजपा ने विकास को बताया विजेता, कांग्रेस ने बदलाव को माना संकेत

उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में भाजपा और कांग्रेस दोनों नेताओं ने जीत का दावा किया और अपनी-अपनी सफलता के स्वर गूंजाए। भाजपा के लिए यह परिणाम आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहा, जबकि कांग्रेस ने हार के बावजूद राष्ट्रीय पार्टी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने पार्टी की योजनाओं और विकास कार्यों पर भरोसा जताया है। उन्होंने मतदाताओं को ग्रामीण विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए भी धन्यवाद दिया। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने दावा किया कि पार्टी ने पंचायत चुनावों में व्यापक जीत दर्ज की है, और जनता ने भाजपा सरकार के कामकाज पर भरोसा दिखाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि लोगों ने भाजपा की नीतियों, विशेषकर महिला सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से निराश होकर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को समर्थन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। कांग्रेस का कहना था कि गांव स्तर पर उनकी रणनीति ने असर दिखाया है, और यह आगामी विधानसभा चुनावों में एक मजबूत आधार तैयार करता है। इसके अलावा, कई भाजपा नेताओं को इस चुनाव में व्यक्तिगत स्तर पर झटका लगा। एक भाजपा विधायक के बेटे संतोष कुमार नौगांव सीट से हार गए, वहीं उनकी पत्नी पूजा देवी भी डूंगरलेख सीट हार बैठी। भाजपा के कई अन्य दिग्गज नेताओं के परिवारों को भी करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे पार्टी के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। निर्दलीयों की बड़ी उपस्थिति ने चुनावी समीकरण ही बदल दिए। कई वरिष्ठ नेता-परिवारों को सहयोग मिलने के बावजूद जनता ने स्थानीय, काम वाले उम्मीदवारों को ही चुना। सीमा भंडारी (सीला दुगड्डा सीट), लच्छू भाई (बीडीसी सदस्य), पिथौरागढ़ की युवा प्रधान प्रियंका नेगी जैसी जीतों को कांग्रेस ने लोकतंत्र की जीत बताया, जबकि भाजपा ने उनका स्वागत करते हुए जनता की बदलती प्राथमिकताओं को स्वीकार किया। इस पूरे चुनाव ने दिखाया कि ग्रामीण मतदाता अब सिर्फ दलों तक सीमित नहीं हैं, वे उम्मीदवार की छवि, कामकाज और स्थानीय जुड़ाव पर भरोसा करते हैं। भाजपा ने दावा किया कि उसका ग्रासरूट प्रभाव साफ दिखा, वहीं कांग्रेस ने कहा कि उसका संगठन धीरे-धीरे गांवों तक पहुंच रहा है और यह सफलता सिर्फ शुरुआत है।

शिक्षक भर्ती और लंबित मामलों को लेकर रीजनल पार्टी ने शिक्षा मंत्री से की मुलाकात

देहरादून, 2 अगस्त 2025: डीएलएड शिक्षकों की भर्ती और एलटी शिक्षकों के कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर आज राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से मुलाकात की। पार्टी ने प्राथमिक शिक्षा विभाग में शीघ्र भर्ती शुरू करने और एलटी शिक्षकों से संबंधित कोर्ट के मामलों को निपटाने की मांग की। इस दौरान डीएलएड और आईटी शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने हाई कोर्ट के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर से फोन पर बात की और उन्हें 5 अगस्त को होने वाली कोर्ट सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का अनुरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग को एलटी शिक्षकों की भर्ती से कोई आपत्ति नहीं है और इस मामले को जल्द निस्तारित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 2700 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि उनकी पार्टी बेरोजगारों और शिक्षकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और हर स्तर पर उनकी पैरवी की जाएगी। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की अपील की।

सांसद त्रिवेंद्र रावत को जीरो नम्बर दिए वीरेंद्र रावत ने!

डॉ श्रीगोपाल नारसन
एडवोकेट

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे और हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत ने बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जुबानी हमला बोला है, वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत पर क्षेत्र से नदारद रहने के आरोप लगाया है। पिछले दिनों वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद त्रिवेंद्र रावत को कई और मामलों पर भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उन्हें व उनकी पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया। वीरेंद्र रावत ने महंगाई और प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर कई सवाल उठाए, साथ ही वीरेंद्र रावत ने कहा कि पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर जिस तरह क्षेत्र और लोगों के बीच नदारद रहने के आरोप लगते थे, उसी तरह वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए भी पिछले एक साल में पोस्टर लगाए गए हैं। उनके अनुसार जनता ने कई जगहों पर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को ढूंढने पर इनाम तक घोषित कर रखा है। वीरेंद्र रावत का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरिद्वार के लिए 72 सूत्रीय कार्यक्रमों का मेनिफेस्टो जारी किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे, इसीलिए उन्होंने अपना मेनिफेस्टो सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा था, ताकि जनता की भलाई के काम सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के जरिए हो सकें, लेकिन सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक भी कार्य अब तक नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि 10 में से 0 नंबर ही मैं सांसद के कार्यकाल को दूंगा।

वही उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का जमीन घोटाला भी इन दिनों चर्चाओं में है। आरोप है कि जिस जमीन को कोई लाख रुपए में भी नहीं खरीदता था, उस जमीन को हरिद्वार नगर निगम के अधिकारियों ने 54 करोड़ रुपए में खरीद लिया। जो एक बड़ा घोटाला है, इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट भी शासन को भेजी जा चुकी है, लेकिन जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। हरिद्वार जमीन घोटाले को लेकर जब उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर तो कार्रवाई हो ही, लेकिन परदे के पीछे कौन लोग हैं यह भी सामने आना चाहिए। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर बात है कि इतने बड़े अधिकारी कैसे इतनी लापरवाही कर सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस मामले में जांच पूरी हो गई है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है, यह स्पष्ट नहीं है। लिहाजा सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी ऐसी हरकत करने से पहले दस बार सोचे, यदि अधिकारी ने किसी की शय पर ये काम किया हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मामले में कुछ अधिकारियों का निलंबन करके इतिश्री कर दी गई। हरिद्वार जिले में आचार संहिता के दौरान नगर निगम ने साल 2024 में 33 बीघा जमीन खरीदी थी। बताया जाता है कि इस जमीन की कीमत कुछ लाख रुपए बीघा थी, लेकिन निगम और जिले के कुछ अधिकारियों ने कृषि भूमि को 143 में दर्ज करवाकर 58 करोड़ रुपए में खरीद लिया था।

मामला प्रकाश में आने के बाद घोटाले की आशंका जताई गई, मामला सीएम दरबार तक पहुंचा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की जांच के आदेश देते हुए कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई की और इस पुरे मामले पर जांच बैठा दी थी, जांच कर रहे आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने जांच पूरी करके रिपोर्ट शासन को भी सौंप दी है। ऐसे मे स्वयं भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बयान देते है कि 'हरिद्वार वह जिला है, जहां पर मुख्यमंत्री हफ्ते में एक बार तो आते ही हैं, दुनिया भर से लोग है हरिद्वार में आते हैं, मैं हरिद्वार का सांसद हूं, इसीलिए हफ्ते में दो से तीन दिन हरिद्वार जाता हूं। फिर भी अधिकारी इस तरह का घपला करते हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में जमीन से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऋषिकुल की भूमि हो या मेला क्षेत्र की, इन जमीनों की भी कुछ सरकारी अधिकारियों ने बंदरबांट करने की कोशिश की है। हरिद्वार में जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं। इसीलिए अधिकारी कुछ लोगों के साथ मिलकर जमीनों की बंदरबांट करने में लगे हुए हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले से हरिद्वार और राज्य की छवि खराब हो रही है। 'सवाल उठता है सरकार स्वयं भाजपा सांसद त्रिवेंद्र रावत की पार्टी की है, फिर चाहे राज्य में हो या केंद्र में ऐसे में घोटाला चाहे अधिकारी करे या कोई ओर जिम्मेदारी तो उनकी भी सरकार का जनप्रतिनिधि होने के नाते बनती

है। तभी तो कांग्रेस ने पूछा है कि जांच के बाद क्या हुआ? त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के बाद कांग्रेस भी अब इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है, फिर भी सरकार जांच क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले से यह साफ जाहिर हो गया है कि राज्य में अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से किस तरह से घपले और घोटाले हो रहे हैं। इस मामले पर तुरंत कोई एक्शन होना चाहिए वरना जांच का कोई फायदा नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खनन को लेकर भी अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोला है, हाल ही में संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक निजी चौनल पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते' उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान खनन सचिव बृजेश कुमार संत के उस दावे के बाद आया है, जिसमें संत ने कहा था कि उत्तराखंड में पिछले 25 वर्षों में इस साल सबसे अधिक खनन राजस्व प्राप्त हुआ है। ब्रजेश कुमार संत ने आंकड़े पेश करते हुए कहा था कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को खनन से लगभग 1100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि राज्य के गठन के बाद का अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। राजस्व सचिव का यह बयान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाने के बाद आया है। जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल किया था कि इस खनन पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। रावत का आरोप था कि अवैध खनन के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर सख्ती नहीं बरत रही। जो सीधे सीधे राज्य की भाजपा सरकार को घेरना ही कहा जायेगा। इस पर खनन सचिव बृजेश कुमार संत ने बयान जारी कर दावा किया था कि खनन से होने वाला राजस्व पिछले वर्षों की तुलना में इस साल सबसे अधिक रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए सरकार ने टेक्नोलॉजी और टास्क फोर्स का सहारा लिया है, जिससे चोरी का खनन रुका है और राजस्व में इजाफा हुआ है। संत ने कहा, 'आज तक जब भी वित्त विभाग ने टारगेट दिया, हमने उसे न केवल पूरा किया, बल्कि 200 करोड़ रुपये ज्यादा सरप्लस राजस्व जुटाया। 'बृजेश कुमार संत ने ट्रकों के रात में चलने को लेकर भी सफाई भी दी,उन्होंने कहा कि स्टोन क्रेशरों से निकलने वाला माल वैध रूप से ही निकलता है। उन्होंने कहा, 'रात में ट्रकों के चलने का कारण अवैध खनन नहीं बल्कि यातायात का दबाव कम करना है।' दिन में तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की आवाजाही के कारण ट्रकों का निकलना मना है, ताकि हादसों की संभावनाएं कम रहें।

खनन सचिव के इस बयान के बाद जब दिल्ली में एक निजी चैनल की पत्रकार ने त्रिवेंद्र रावत से इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने तल्ख अंदाज में कहा, 'शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते।' हालांकि, रावत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान अधिकारियों पर तंज माना जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ही सरकार की पोल खोल रहे हैं, जिससे साफ हो गया है कि उत्तराखंड में खनन माफिया हावी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा नेता ही सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, इससे साफ है कि सरकार के दावे खोखले है।

त्रिवेंद्र सिंह रावत का लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर होना पार्टी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। भाजपा नेताओं का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। राज्य में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की बयानबाजी और कांग्रेस के हमले से भाजपा की स्थिति असहज होती दिख रही है।

(लेखक ज्वलंत मुद्दों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार है)

बीएड प्रवेश परीक्षा का वर्तमान नोटिफिकेशन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़- डॉ. सुनील अग्रवाल

डॉ. सुनील अग्रवाल

निजी कॉलेज एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल ने शासन द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा के के लिए जारी नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब अगस्त माह में जब छात्रों की कक्षाएं शुरू होनी थी तब प्रवेश परीक्षा हेतु 28 जुलाई का नोटिफिकेशन छात्रों के एक वर्ष को बर्बाद कर देगा उन्होंने कहा कि जिन छात्रों को कोई कोर्स करना होता है वह इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करता अगर प्रवेश परीक्षा करनी थी तो मई के महीने में हो जानी चाहिए थी सरकार का ढुलमुल रवैया छात्रों का 1 वर्ष खराब करने वाला और कॉलेजों को बंदी के कगार पर लाने वाला साबित होने वाला है अब 28 जुलाई को तो नोटिफिकेशन हुआ है अभी प्रवेश परीक्षा के लिए कब आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे कुछ निश्चित नहीं है फिर प्रवेश परीक्षा की तिथि निश्चित होगी और प्रवेश परीक्षा के उपरांत परिणाम घोषित होगा इस सब में दो महीने का समय यानी ऐसे में कक्षाएं नवंबर दिसंबर माह में ही प्रारंभ हो पाएंगी ऐसे में छात्र कोर्स करने हेतु अनयंत्र पलायन को विवश होंगे और बी.एड कॉलेज जो पिछले कुछ वर्षों से छात्रों के अभाव में बंदी के कगार पर हैं अब पूर्णतया बंदी की ओर अग्रसर होंगे उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ आई है तब से सरकार का रवैया निजी कॉलेजों के संबंध में संवेदनहीन हो चुका है। एक समय था जब सरकार का रवैया निजी कॉलेजों के प्रति सकारात्मक था लेकिन अब पूरी तरह से नकारात्मक हो चुका है। ऐसे में इन कॉलेजों में कार्यरत शैक्षणिक और अन्य स्टाफ पर बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर अग्रवाल ने सरकार से आग्रह किया की छात्र हित में अविलंब प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

पाँचवें दिव्य हिमगिरि टॉपर्स कॉन्क्लेव में 271 छात्रों को दिए मेडल और अवॉर्ड सर्टिफिकेट

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने टॉपर छात्रों से नशामुक्त समाज बनाने का आह्वान किया

यूकॉस्ट, डीआईटी यूनिवर्सिटी एवं दून डिफेंस एकेडमी के सहयोग से आयोजित हुआ टॉपर्स कॉन्क्लेव

देहरादून के आईसीएसई एवं सीबीएसई स्कूल के टॉपर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उत्तराखंड शासन के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सफलता और असफलताएं दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि असफलताओं से कभी नहीं डरना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने कर्म को ऑडिटर बताते हुए आगे के जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही।

उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार, आईएएस देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में यूकॉस्ट, दिव्य हिमगिरी एवं डीआईटी यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पांचवें टॉपर्स कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि अभी तो जीवन शुरू हुआ है, आपको कई लक्ष्यों पर विजय प्राप्त करनी है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। स्वस्थ जीवन है तो सब कुछ है। इसके लिए उन्होंने देश के भविष्य टॉपर्स छात्रों को नसीहत देते हुए कहा कि 'नशे को ना कहें'। नशा जीवन का कभी भी अंग नहीं बनना चाहिए। 'ना' का मतलब ना, ना और ना ही होना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि यदि वह कभी महसूस करें तो बच्चे का डांटने की बजाय उनकी काउंसलिंग करवाएं। डॉ राजेश ने टॉपर छात्रों का उत्साहवर्द्धन करते हुए उन्हें स्कूली जीवन के बाद सफलता प्राप्त करने के मंत्र बताए।

इस कॉन्क्लेव में 25 स्कूलों के 271 बच्चों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल तथा अवार्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 25 स्कूलों को बेस्ट स्कूल के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. (डॉ.) दुर्गेश पंत ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी समृद्ध है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में ढाई सौ वर्ष पूर्व सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार देश की शीर्ष संस्थाएं आईआईआरएस, आईआईपी वाइल्डलाइफ इंस्टीटयूट, एफआरआई, रूड़की आईआईटी जैसी तमाम संस्थाएं यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि देश की पांचवी साइंस सिटी भी देहरादून में शीघ्र बनकर तैयार होने वाली है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के चलते आज राष्ट्र निर्माण के लिए आप जैसे उत्कृष्ट छात्रों की देश को

जरूरत है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआईटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.(डॉ.) जी. रघुराम ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आपने जो ऊंचाई आज स्कूली जीवन में प्राप्त की है, वही ऊंचाइयां आप भविष्य में अपने जीवन के हर रास्ते में प्राप्त करते रहें, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं आईआईआरएस के निदेशक डॉ. आर.पी. सिंह ने टॉपर्स बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। दून डिफेंस अकादमी के निदेशक संदीप गुप्ता ने टॉपर्स को कहा कि वह जीवन में अपने अभिभावकों एवं अध्यापकों के योगदान को हमेशा स्मरण करें। कार्यक्रम को प्रिंसीपल्स प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कश्यप तथा डॉ. मोहित नागपाल ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम के संयोजक डॉ. कुँवर राज अस्थाना ने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा बताई और भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। इससे पूर्व सभी अतिथियों ने टॉपर्स कॉन्क्लेव स्मारिका एवं यंग साइंटिस्ट एंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव के पोस्टर का विमोचन किया। टॉपर्स कॉन्क्लेव स्मारिका में 25 स्कूलों के 271 बच्चों के रिजल्ट का दस्तावेजीकरण किया गया है। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन विज्ञान संप्रेषण के सह संपादक डॉ. विशाल कौशिक द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन डीआईटी यूनिवर्सिटी के डीन डॉ. नवीन सिंघल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 25 स्कूलों के प्रधानाचार्य, मैनेजमेंट के प्रतिनिधियों के अलावा काफी संख्या में अभिभावक एवं छात्र मौजूद थे।

10वीं कक्षा के टॉपर

10वीं के टॉपर पार्थ गुप्ता, अनाया ठक्कर, प्रत्युंजय कोहली, ईशान यादव, रणदीप सिंह, आरना शर्मा, शिवांग सिंह, श्रीजय नेगी, नेहल सर्पा, युक्ता मंडल, शुभी सिंह, कनिका कंडवाल, नाव्या खंडूरी, आलेख्या शाह, जान्हवी, अनाय कश्यप, श्वेता असवाल, गुंजन, मानसी कुशवाह, हर्ष पांडेय, भाव्याश्री कुमार, सार्थक धस्माना, मान्या गर्ग, आर्यन बिष्ट और दक्ष जैन को मिला उत्कृष्टता पुरस्कार

12वीं कक्षा के टॉपर

12वीं के टॉपर शौर्य अग्रवाल, लावन्या दास, पंखुडी भंडारी, हर्षिल ऋषि राज, रेहा गुप्ता, गौरी सिंघल, सारांश मित्तल, गार्गी खुगशाल, वैष्णवी गर्ग, जसलीन कौर मेहता, कनक कपूर, वेदांत जोशी, आद्या सिंह, वंश सिरोही, अर्शजोत कौर, लक्ष्य गोयल, ईशिता शर्मा, अनुवंशी गुप्ता, समृद्धि बधानी, अविरल मक्कर, मान्या जायसवाल, मन्नत गर्ग, जेनब आजिम, रेखा पंवार, आंचल माटा, मानवी मलिक, शगुन आनंद, रिजा खान, नेहा, ईशित कोहली, निखिल कुमार सिंह, असर्था नागाकोटी, अनुष्का गुप्ता, नेहा नेगी, महिमा रावत, अंशिका डंगवाल, वंशिका चौहान, दिव्यांशु सोनकर, विदिशा सेमवाल, तेजस भटनागर, आर्या आदित्या, आइशा राणा, स्तुति कुमारी, आर्यन बिष्ट, ईशा ढल्ला और सोमेश अग्रवाल को मिला उत्कृष्टता पुरस्कार

25 स्कूलों को मिला बेस्ट स्कूल का अवॉर्ड

1. सेंट जोसेफ अकादमी, 2. कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी, 3. ब्राइटलैंड्स स्कूल, 4. कार्मन रेसिडेंशियल एंड डे स्कूल, 5. कैम्ब्रियन हॉल, 6. श्री राम सेंटेनियल स्कूल, 7. द मोंटेसरी स्कूल, 8. दून इंटरनेशनल स्कूल, 9. द टोंसब्रिज स्कूल 10. कसीगा स्कूल, 11. इकोले ग्लोबल इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, 12. हिम ज्योति स्कूल, 13. द एशियन स्कूल, 14. शिक्षांकुर द ग्लोबल स्कूल, 15. दून वैली इंटरनेशनल स्कूल, 16. द पेस्टल वीड स्कूल, 17. पीएम श्री केवी एलबीएसएनएए मसूरी, 18. सेंट कबीर अकादमी, 19. सनराइज अकादमी, 20. द चिल्ड्रन्स अकादमी, 21. माँ आनंदमयी मेमोरियल स्कूल, 22. द इंडियन पब्लिक स्कूल 23. एस एन मेमोरियल पब्लिक स्कूल, 24. वैंटेज हॉल 25. एसजीआरआर पब्लिक स्कूल

परीक्षा परिणाम आधरित देहरादून के 25 बेस्ट आईसीएसई/सीबीएसई स्कूल

5TH TOPPERS' CONCLAVE
Award Ceremony of
Meritorious Students & 25 Best Schools of Dehradun
5th TOPPERS' CONCLAVE
5th TOPPERS' CONCLAVE
दिव्य हिमगिरि
DIT
25

5TH
CONCLAVE
Meritorious
दिव्य हिमगिरि
5th TOPPERS' CONCLAVE

दिव्य हिमगिरि
DIT
5TH
Meritori

5TH
CONCLAVE
DIT

दिव्य हिमगिरि
DIT
5TH
5th TOPPERS' CONCLAVE

5TH TOPPERS' CONCLAVE
Award Ceremony of
Meritorious Students & 25 Best Schools of Dehradun
5th TOPPERS' CONCLAVE
25

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

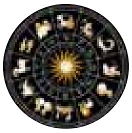
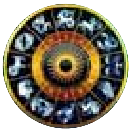
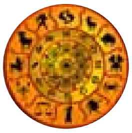

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- आज ग्रहों की स्थिति आपके लिए फायदेमंद बनी हुई है। आप जो भी मेहनत करेंगे, उसका भविष्य में बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपको अच्छे काम मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी कागज या दस्तावेज पर बिना पढ़े दस्तखत न करें। घर का माहौल खुशनुमा और शांत रहेगा। शुगर और ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है, लापरवाही न करें। भाग्यशाली रंग- ऑरेंज

वृषभ राशि- अपनी ही काम करने की क्षमता पर विश्वास रखें। युवाओं का कोई सपना अधूरा रहने की वजह से मन कुछ उदास रहेगा। यह समय शांति और धैर्य से बिताने का है। पति-पत्नी छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, काम का बोझ और तनाव लेने से ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। भाग्यशाली रंग- लाल

मिथुन राशि- आपकी अच्छी कार्यप्रणाली की वजह से सामाजिक गतिविधियों में आपकी छवि चमकेगी। इस समय किसी भी तरह की यात्रा न करें। संतान के भविष्य को लेकर कोई चिंता रह सकती है। अधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें। पति-पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। दिनचर्या व खान-पान को व्यवस्थित रखे। भाग्यशाली रंग- लाल

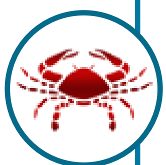

कर्क राशि- पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी। किसी काम को मजबूरी में करना पड़ सकता है और ऐसा करना आपको तनाव भी देगा। मुश्किल परिस्थितियों में घबराने की बजाय धैर्य और शांति से समय बिताएं। सफलता पाने के लिए थोड़ा स्वार्थी भी होना जरूरी है। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। भाग्यशाली रंग- सफेद

सिंह राशि- घर के बड़े सदस्यों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें। भाइयों के साथ संबंधों में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। रिश्तों को संभालने में आपका योगदान जरूरी है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से खुशी होगी। अपनी मन:स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ध्यान और मेडिटेशन जरूर करें। भाग्यशाली रंग- क्रीम

कन्या राशि- धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। किसी करीबी संबंधी के साथ किसी खास मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत भी होगी। कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लें। बहुत ज्यादा भावुकता भी नुकसानदायक रह सकती है। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर लापरवाह न बनें। शादीशुदा संबंधों में मधुरता रहेगी। भाग्यशाली रंग- हरा

तुला राशि- युवा अपने करियर को लेकर गंभीर रहेंगे। किसी संबंधी के साथ निजी समस्याओं को लेकर बहस हो सकती है। किसी राजनैतिक अथवा अनुभवी व्यक्ति की सलाह व मदद आपके काम को नई दिशा देगी। परिवार के साथ कुछ समय मनोरंजन और शक्रपिंग में बिताने से आपसी संबंधों में नजदीकियां और मधुरता आएगी। भाग्यशाली रंग- जामुनी

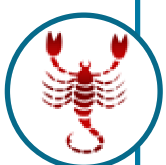

वृश्चिक राशि- विद्यार्थी तथा युवा वर्ग को अपनी मेहनत के अनुसार बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। साझेदारी के काम में पार्टनर की योजनाएं व कार्यशैली काम के लिए फायदेमंद साबित होंगी। परिवार के सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार की गलतफहमी न उत्पन्न होने दें। अनियमित दिनचर्या की वजह से एसिडिटी की शिकायत रहेगी। भाग्यशाली रंग- लाल

धनु राशि- नजदीकी संबंधी के माध्यम से अच्छी खबर मिल सकती है। ध्यान रखें कि छोटी सी लापरवाही भी आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। इस समय नौकरीपेशा लोगों के ऊपर काम का बहुत ज्यादा बोझ रहेगा, समय को धौर्य पूर्ण तरीके से बिताएं। प्रेमी-प्रेमिका के लिए भी मुलाकात का अवसर बनेगा। भाग्यशाली रंग- पीला

मकर राशि- अपनी प्रतिभा से समाज तथा काम में अलग पहचान बनाएंगे। घर में सुख-सुविधा से जुड़ी किसी महंगी वस्तु की खरीदारी संभव है। अपनी चीजों की अच्छी तरह देखभाल करें, चोरी होने या गुम होने का खतरा है। किसी भी महत्वपूर्ण काम को करते समय परिवार के सदस्यों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें। शादीशुदा संबंध मधुर रहेंगे। भाग्यशाली रंग- आसमानी

कुंभ राशि- धैर्य और संयम से अपनी मन:स्थिति को संतुलित रखें। अन्य गतिविधियों में व्यस्तता की वजह से अपने निजी कामों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। सरकारी नौकरी में अपने लक्ष्य को पूरा करने में बड़े अधिकारियों की भी मदद मिलेगी। प्रेम संबंधों को शादी के लिए परिवार की मंजूरी मिल सकती है। पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिएं। भाग्यशाली रंग- हरा

मीन राशि- व्यस्तता के बावजूद आप अपनी रुचि से जुड़े कामों के लिए भी समय निकाल लेंगे। ध्यान रखें कि गुस्से और ईगो की वजह से आपके हाथ से कोई खास सफलता निकल भी सकती है। किसी भी मुश्किल हालात में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। नियमित जांच भी करवाते रहें। सावधानी बरतने से स्वस्थ रहेंगे। भाग्यशाली रंग- गहरा पीला

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Silkyara™

हिमालय का वरदान

बद्री गाय का घी

उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली बद्री गाय जिसको "कामधेनु" भी कहा जाता है, का परंपरागत रूप से बनाया गया घी अब देहरादून में भी उपलब्ध है

- A2 प्रोटीन युक्त
- औषधीय गुणों से भरपूर
- इम्युनिटी बढ़ाने में लाभदायक
- पाचन में हल्का और बाल विकास में सहायक

कुमार स्वीट्स

- सहस्त्रधारा रोड, निकट क्रॉसिंग
- धर्मपुर, निकट एलआईसी बिल्डिंग

पर उपलब्ध है।

fssai 22623030001586

UDYOG AADHAR MSME UK050061483

THE DOON HIMALAYAN AGRO FOODS
Dehradun
Lokesh Asthana - 7409782771